an>

Title: Need to formulate a scheme for supply of water in villages facing scarcity of water and also launch start-ups for power-generation through solid and liquid waste management in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) ः देश में गंदगी के खिलाफ जंग का बिगुल फूंकते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगभग ढाई साल पहले "स्वच्छ भारत मिशन " की शुरुआत की थी। इसका नतीजा निचले स्तर पर दिखने लगा है। गांवों से लेकर शहरों तक चलाए जा रहे इस अभियान से लोग जुड़ने लगे हैं। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विश्व बैंक की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 फीसदी नुकसान गंदगी से हो रहा है। गंदगी से होने वाली बीमारियों से मौत हो रही है। साथ ही लोगों की कार्यक्षमता भी गिर रही है। इसका सीधा नुकसान अर्थव्यवस्था का हो रहा है।

"स्वच्छ भारत मिशन " के मुख्य रूप से 3 आयाम हैं। पहला, हर घर में शौचालय का निर्माण। दूसरा, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय परिसर बनाना और तीसरा, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन। शौचालय निर्माण की दिशा में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उत्साहजनक सफलता मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मार्च, 2017 के अंत तक देश के 100 से अधिक जिले खुले शौच से मुक्त हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2019 तक देश के सभी घरों में शौचालय का निर्माण करना है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में कमी तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन है।

इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि देश में पानी की कमी वाले गांवों की पहचान करके उन्हें जल ग्राम योजना के तहत जल क्रांति अभियान से जोड़कर पानी की कमी को पूरा किया जाए तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के द्वारा ऊर्जा पैदा करने हेतु युवाओं को स्टार्ट-अप शुरु करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।